**Fourteenth Loksabha**

**Session : 6**
**Date : 29-11-2005**

**Participants : Chandel Shri Suresh**

>

Title : Need to roll back hike in rates being charged for medical treatment by PGI, Chandigarh.

**श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.)** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की तरफ आकृट करना चाहता हूं। यह संस्थान पूरे उत्तर-भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, लेकिन जो मरीजों की जांच-परख के लिए शुल्क लिया जाता है, उसमें पिछले दिनों काफी वृद्धि कर दी गई है, जिसके कारण उस संस्थान में दाखिल होने वाले मरीजों की संख्या भी कम हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 29 सितम्बर, 2002 को गवर्निंग बॉडी के अंदर यह निर्णय लिया गया कि वहां यह शुल्क न बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बावजूद, बिना गवर्निंग बॉडी के अंदर उस विाय को ले जाए बगैर, शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस कारण आज स्थिति यह है कि एम्स, जो दिल्ली में स्थित है, उससे भी ज्यादा शुल्क वहां ओपीडी और  जनरल वार्ड में जो गरीब लोग आते हैं, उनसे लिया जा रहा है। जैसा मैने कहा कि इस कारण वहां मरीजों की संख्या कम हो रही है और उन्हें शुल्क के कारण बड़ी तकलीफ हो रही है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब  वहां भारत सरकार 200 करोड़ रुपए साल का खर्च कर रही है और दूसरी तरफ यह कोशिश हो रही है कि गरीब लोग उस संस्थान के दरवाजे तक न पहुंच पाएं, यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि हम मानवीय चेहरे लेकर काम करेंगे, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि किसी संवैधानिक संस्थान में ऐसे कुछ निर्णयों को, बिना गवर्निंग बॉडी की अनुमति लिए, वहां लागू कर दिया गया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इसमें इंटरवीन करें और वहां जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय दिलाने में पहल करें। उन शुल्कों को वापस लिया जाए।